**The Tribune** 8 June, 2017

# Assocham report rips apart govt claims on Gurugram

SUSHIL MANAV
TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JUNE 7

At a time when the Haryana Government boasts of attracting new investments, the report "Gurugram: From Millennium City To An Infrastructure Mess" released by Assocham today, rips apart its claims that it has been providing an environment conducive to the growth of business and industry.

The study report prepared by the economic research bureau of Assocham highlights several drawbacks that have collectively robbed Gurugram of its Millennium City tag and led to numerous problems like lack of power and drinking water, poor sewerage and drainage and mobility bottlenecks.

The report says over the years, Gurugram has emerged as the most developed commercial and business centre of Haryana due to its geographical location and other factors.

Such has been Gurugram's dominance that it has 19.6 per cent share of total factories in the state, 32.6 per cent share in employment generation, 24.9 per cent share in VAT realisation and 53.5 per cent share in state's receipts from entertainment tax.

With Rs 4,51,367 crore of Haryana's outstanding investment of Rs 6,47,955 crore, Gurugram's share in the state this year stands at 69.7 per cent compared to 19.5 per cent in 1995-96.

However, the report observes that infrastructural development in Gurugram is grossly inadequate to match the industrial development that has been witnessed in the past few decades.

With rapid industrial development and robust job generation by the industrial and service sectors, the Gurugram population had grown by over 500 per cent in a decade.

Statistics suggest that on an average, about four lakh vehicles enter and exit the city everyday. Along with traffic burden, there is a significant shortage in traffic police strength, making it very difficult to manage the city's huge traffic volume.

Moreover, the report has observed that faulty engineering and lack of coordination among various departments (MC, HUDA and DTCP) aggravate the problem.

The Assocham report, quoting official estimates, observes that the total water demand is 82 million gallons a day (MGD) while the supply stands at 61 MGD.

It further says on an average, between 1,250 and 1,300 MW of power is required during summer, but the gap between demand and supply seems to be widening over a period of time.

On the issue of sewerage in Gurugram, the report says the city is generating around 140 millions litres a day (MLD) of sewage, besides nearly 20,000 MLD and 10,000 MLD, by unregistered and registered bore wells, respectively. However, the sewage treatment plants in Behrampur and Dhanwapur have a combined capacity of only 118 MLD.

Umesh Agarwal, BJP MLA from Gurugram, claimed that only private builders had been given the benefits of development during 10 years of the previous Congress regime. "Now, we have started infrastructural development by laying the KMP expressway and NPR Dwarka expressway, besides taking up other projects," he said.

**Business Standard** 8 June, 2017

# India Inc disappointed as rates unchanged

As the Reserve Bank of India (RBI) left lending rates unchanged, India Inc on Wednesday expressed disappointment, saying the central bank had chosen to remain over-cautious about the inflation outlook.

Industry chamber Assocham said the RBI had "disappointed India Inc" by not reducing the policy interest rates, especially when inflation remained quite benign.

"It is clear that the RBI has chosen to remain over-cautious about the inflation outlook even when the key data like crude oil, monsoon, and the inability of the producers to hike prices made a clear-cut case for softening of the interest rates," it said in a statement. It also said a large part of industry was reeling under heavy debt and the high interest costs were becoming a big drag on the balance sheets.

"The deceleration in growth in the last quarter of 2016-17 also underscores the need for lesser cost of money," it said. "...you cannot find fault with the RBI when its main mandate has been to keep inflation low, and not growth dynamics. However, even at this point of time, the data itself was so supportive of a rate cut, which did not happen pitifully," it added.

PTI

The Indian Express

8 June, 2017

"GDP numbers clearly reflect the effect of demonetisation panning out in Q4. At this juncture, RBI signalling a move towards an accommodating stance would have helped uplift the sentiment"

FICCI

"It is clear that the RBI has chosen to remain over-cautious about the inflation outlook even when key data like crude oil, monsoon, inability of the producers to hike prices made a clear case for softening of the rates"

ASSOCHAM

**ASSOCHAM IN THE NEWS**

**Dainik Jagran National Edition** **8 June, 2017**

मौद्रिक नीति की समीक्षा ▶ महंगाई की स्थिति कमोबेश अच्छे रहने के आसार

# आरबीआइ ने नहीं घटाया रेपो रेट

## फिर भी होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की बन सकती है सूरत

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

बुधवार को वार्षिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को घटाने से अभी इन्कार कर दिया है। महंगाई को लेकर बेहद सतर्क रहने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आरबीआइ गवर्नर उर्जित पटेल ने आशंका जताई है कि महंगाई की दर आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने वैधानिक दर 'रेपो रेट' को 6.25 फीसद पर बरकरार रखा है। इस फैसले के लिए आरबीआइ कई वजहें बताई हैं। इसमें एक किसानों की कर्ज माफी भी है।

आरबीआइ ने सीधे तौर पर ब्याज दरों को नहीं घटाया है, लेकिन उसने कुछ ऐसे उपाय जरूर किए हैं, जो आने वाले दिनों में कर्ज को सस्ता को करने में मदद कर सकती हैं। मसलन, वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर में 0.5 फीसद की कटौती कर 20 फीसद करने का फैसला किया गया है। इससे बैंकों के पास और ज्यादा राशि कर्ज बांटने के लिए बचेगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि बैंकों के पास पहले से ही काफी नकदी है। ऐसे में इसका असर ब्याज दरों पर पड़ेगा, कहना मुश्किल है। इसी तरह से आरबीआइ ने आवास ऋण को लेकर एक कदम यह उठाया है कि अब बैंकों को होम लोन देने पर कम राशि समायोजित करनी होगी। अभी तक जितनी राशि बैंक होम लोन के लिए देते थे, उसका 0.40 फीसद एक फंड में संरक्षित रखना पड़ता है। इसे घटाकर 0.25 फीसद कर दिया गया है। इससे बैंकों के पास होम लोन के लिए ज्यादा राशि बचेगी और कर्ज सस्ता हो सकता है।

**अर्थव्यवस्था की चुनौतीपूर्ण तस्वीर** : इसके साथ ही आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था की चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करते हुए आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को भी घटाकर 7.3 फीसद कर दिया है। महंगाई दर को लेकर अनुमान लगाया गया है कि पहले छह महीने में तो यह दो से 3.5 फीसद के बीच रहेगी, मगर बाद के छह महीनों में यह बढ़कर 4.5 फीसद हो सकती है। यह पूरी स्थिति बताती है कि केंद्रीय बैंक ने भले ही सीधे तौर पर अभी ब्याज दरों को घटाने के उपाय नहीं किए हों, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है।

**कुछ ने किया स्वागत, कुछ निराश** : आइसीआइसीआइ बैंक की एमडी व सीईओ चंदा कोचर का कहना है कि ब्याज दरों में नरमी का संकेत स्वागतयोग्य कदम है। फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल का कहना है कि आरबीआइ ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में कर्ज की दरों में नरमी आ सकती है। वैसे, एसोचैम ने ब्याज दरों में कटौती नहीं करने पर अफसोस जताया है। उसका कहना है कि आरबीआइ जरूरत से ज्यादा सतर्क है। कई और उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि अगर ब्याज दर कम होती तो उन्हें राहत मिलती।

### क्या है एसएलआर

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बैंकों को जमा राशि का वह निर्धारित न्यूनतम हिस्सा है जो उन्हें अनिवार्य रूप से बांड व ट्रेजरी जैसी सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना होता है। एसएलआर घटाकर 20 फीसद करने का मतलब हुआ कि बैंक अगर 100 रुपये जमा स्वीकार करते हैं तो इसमें से 20 रुपये उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के तौर पर रखना होगा। अभी तक उन्हें 20.50 रुपये रखने पड़ते थे।

### क्या है रेपो रेट

वह दर है, जिस पर बैंक अल्पकालिक जरूरतों के लिए आरबीआइ से कर्ज लेते हैं।

| समीक्षा की खास बातें |
| --- |
| केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 6.25 फीसद पर यथावत रखा |
| एसएलआर को आधा फीसद घटाकर 20 प्रतिशत किया |
| छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें स्थिर रखने का लक्ष्य |
| महंगाई दर पर नहीं होगा जीएसटी लागू होने का कोई खास असर |
| पहली छमाही में महंगाई दर 2-3.5 फीसद व दूसरी में 3.5-4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान |
| विकास दर का अनुमान 7.4 से घटाकर 7.3 फीसद किया |
| किसानों का कर्ज माफ करने से बढ़ सकता है राजकोषीय घाटा |

Amar Ujala 8 June, 2017

# नहीं घटेंगी मासिक किस्तें मुख्य दरों में बदलाव नहीं

## होम लोन जोखिम भार घटाया, जिससे होम लोन देना हुआ आसान

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।

यदि आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है और रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद ब्याज दरों में कटौती की प्रतीक्षा कर रहे थे तो आपको निराश होना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने आम धारणा के अनुरूप प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे लोन की ईएमआई में भी कोई बदलाव नहीं होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की बुधवार को हुई बैठक में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो दर को 6.25 फीसदी तथा रिवर्स रेपो दर को 6 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। हालांकि सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को आधा फीसदी घटा कर 20 फीसदी कर दिया गया।

**एसएलआर में कटौती का निहितार्थ :** एसएलआर के तहत बैंकों को निर्धारित हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना होता है। इस फैसले से बैंकों के पास अधिक नकदी बचेगी, जिसका उपयोग वे कर्ज देने के लिए करेंगे। इसलिए माना जा रहा है कि अधिक सुविधाओं के सहारे बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास जरूर करेंगे।

### विकास दर अनुमान घटा कर किया 7.3 फीसदी

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास दर अनुमान को भी 7.4 फीसदी से घटा कर 7.3 फीसदी कर दिया है। बैंक ने कहा कि एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख के अनुरूप है। साथ ही यह कदम विकास को समर्थन देने तथा मध्यम अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को 2 फीसदी घट-बढ़ के साथ 4 फीसदी पर रखने के लक्ष्य के मुताबिक है।

### कृषि ऋण माफी राजकोष पर भारी

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि किसानों के कर्ज माफ करने से देश की राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। कृषि ऋण माफी का फैसला राजकोषीय घाटे को काबू में करने की दिशा में पिछले दो सालों में जो काम किया गया है, उसे बेकार कर देगा।

### दरों में कटौती न होने से उद्योग जगत निराश

नई दिल्ली। कर्ज दरें नहीं बदलने पर उद्योग जगत ने निराशा जताई है। एसोचैम ने कहा कि आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों को नहीं घटा कर उद्योग जगत को निराश किया है विशेषकर तब, जब महंगाई कम बनी हुई है। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट गोपाल जीवरजका ने कहा कि दरों में कटौती की उम्मीद थी क्योंकि महंगाई सुविधाजनक स्थिति में है और अच्छे मानसून की संभावना से आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है। एजेंसी